

384

51

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:-प.3(55)नविवि/3/2002

जयपुर, दिनांक: 27 SEP 2010

1. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
2. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्था, जयपुर
(समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिकाओं को प्रेषित करने के क्रम में)
4. सचिव, नगर सुधार न्यास..... (समस्त)

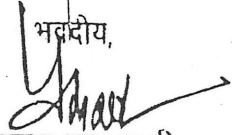
विषय:- नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन करने के लिए निर्धारित मापदण्डों की चैकलिस्ट।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक, चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन करने हेतु जारी नीति दिनांक 19.4.11 जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यासों, राजस्थान आवासन मण्डल एवं समस्त नगरीय निकायों पर लागू है। उक्त आवंटन नीति के अन्तर्गत संस्थाओं को भूमि आवंटन करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर रियायत हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

निर्धारित मापदण्डों की चैकलिस्ट पूर्व में विभागीय पत्र क्रमांक प.3(628)नविवि/3/2011 दिनांक 9.5.2011 द्वारा प्रेषित की गयी थी जिसमें आवेदित भूमि नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्र में स्थित होने संबंधी सूचना सम्मिलित कर पुनः संशोधित चैकलिस्ट प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि ऐसे प्रकरणों में जहां आवेदनकर्ता के अनुरोध पर राज्य सरकार से रियायत दर की अनुमति प्राप्त करनी होगी बावजू प्रत्येक प्रकरण में भूमि आवंटन के प्रस्ताव उपरोक्त निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुरूप तैयार कर चैकलिस्ट के साथ विभाग को भिजवावें।

संलग्न: चैकलिस्ट की प्रतियां

भवदीय,

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

(171)

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/घेराटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को
रियायती दर पर भूमि आवंटन सम्बन्ध निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट
(विभागीय पत्र क्रमांक प.3 (55)नविपि/3/2002 जयपुर
दिनांक ०१ जूलाई २००२ के अन्तर्गत

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

क.स.	आवेदक का नाम/पता	
1.	शहर/कस्बा/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	
2.	चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	
3.	आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	
4.	संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा-जोखा	
5.1	संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	
5.2	चाही गई भूमि के उपयोग सम्बन्ध परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण।	

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

6.2	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा	
6.3	आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस सम्बन्ध नोर्म्स	
7.	क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	
8.	संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	
9.	आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था ने जमा करवायी गई।	
10.	चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
11.	चाही गई अविकसित भूमि के लिए कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर	
12.	चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	
13.	आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण	
13.1	यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनामार्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	
13.2	यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	
14.	आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	
15.	आवेदक संस्था को 30 प्रतिशत दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण	
16.	यदि आवेदक संस्था प्रीमियम संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	
17.	आवंटन करने वाले निकाय का औचित्य	
18.	क्या प्रस्तावित भूमि बागवत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थान आदेश प्रभावी है	
19.	अन्य विवरण	